साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 12, अंक : 10 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 4 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

बदलती जलवायु के दौर में बिगड़ रहा है पानी का संतुलन

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश, वाष्पोत्सर्जन और पानी की उपलब्धता के बदलते संतुलन को समझना अहम बारिश में छोटा सा बदलाव भी जल उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। वैज्ञानिकों ने पाया कि वाष्पोत्सर्जन की एक निश्चित अधिकतम सीमा होती है, जो जलवायु और वनस्पति परिवर्तन से नहीं बढ़ती।

बारिश में छोटा सा बदलाव भी जल उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की कमी से जल संकट तेजी से बढ़ सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ सकता है। आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने पर अतिरिक्त जल से बाढ़ और अचानक बाढ़ की घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। भविष्य की जलवायु नीतियों में केवल वर्षा नहीं, बल्कि वास्तविक जल उपलब्धता को मुख्य मापदंड बनाना आवश्यक है।जलवायु के बारे में बात करते समय लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि कितनी बारिश हुई? यह सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे भी अधिक जरूरी सवाल है कि बारिश के बाद हमारे पास कितना पानी बचता है?

धरती पर पानी एक बजट की तरह काम करता है। जैसे घर में आय और खर्च होता है, वैसे ही प्रकृति में भी पानी की आय और खर्च होता है। पहाड़ों में तेजी से बदल रही है जलवायु, प्रजातियों की विलुप्ति व अरबों लोगों की पानी की आपूर्ति दांव पर बारिश में छोटा सा बदलाव भी जल उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। प्रकृति में पानी की आय का मतलब है बारिश, यानी बारिश और बर्फ। पानी का खर्च का मतलब है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तियों के माध्यम से उसे हवा में छोड़ देते हैं। जमीन पर पानी का अधिकतर नुकसान इसी प्रक्रिया से होता है। इसलिए अगर बारिश ज्यादा हो लेकिन पानी तेजी से उड़ जाए, तो हमारे पास उपयोग के लिए कम पानी बचेगा। बारिश में छोटा सा बदलाव भी जल उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। हाल ही में यह अध्ययन पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन्स प्रकाशित हुआ है। यह शोध वेइजमैन इंस्टीटूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि वाष्पोत्सर्जन की एक अधिकतम सीमा होती है। यानी चाहे मौसम बदल जाए या पेड़ों की संख्या बदल जाए, एक सीमा के बाद पानी का वाष्पीकरण और नहीं बढ़ सकता। यह खोज पहले की धारणाओं से अलग है। पहले माना जाता था कि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण भी लगातार बढ़ेगा। लेकिन इस अध्ययन से पता चला कि इसकी एक निश्चित सीमा है। बारिश में छोटा सा बदलाव भी जल उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जलवायु मॉडलों और लंबे समय के आंकड़ों का उपयोग किया। ये आंकड़े फ्लक्सनेट नामक एक वैश्विक नेटवर्क से लिए गए।

समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों के संबंधित वितरण घोषणा

फार्म - 4

1. प्रकाशक स्थल -209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.)
2. प्रकाशन अवधि -साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम -डॉ. सोनल मेहता
   क्या भारत का नागरिक है - हाँ
   पता- -209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम -डॉ. सोनल मेहता
   क्या भारत का नागरिक है - हाँ
   पता- -209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.)
5. संपादक का नाम -डॉ. सोनल मेहता
   क्या भारत का नागरिक है - हाँ
   पता- -209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो -डॉ. सोनल मेहता
   समाचार पत्र के स्वामी हो तथा
   जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से
   अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो।

मैं डॉ. सोनल मेहता एतद द्वारा घोषित करता हूँ मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर
मार्च 2026 डॉ. सोनल मेहता
(प्रकाशक के हस्ताक्षर

क्या प्लास्टिक कभी खत्म होगा, क्या इससे हमेशा धरती प्रदूषित होती रहेगी?

नई दिल्ली। दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। समुद्र तट पर पड़ा कचरा ही इसका पूरा सच नहीं है। प्लास्टिक टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये पानी, मिट्टी और हवा में फैल जाते हैं। जानवर, पक्षी और इंसान सभी इससे प्रभावित होते हैं।

हर साल लगभग 1.9 करोड़ टन प्लास्टिक नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। यह मात्रा हर साल बढ़ रही है। सफाई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जितना कचरा हटाया जाता है, उससे अधिक फिर से जमा हो जाता है। यह समस्या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती रहती है। यह अध्ययन हेलियोन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। साल 2022 में कई देशों ने मिलकर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया। इसका उद्देश्य प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा करना है। इस ढांचे के लक्ष्य सात में कहा गया है कि 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। फिर भी, सवाल यह है कि जब लक्ष्य तय है, तो ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? प्लास्टिक केवल दिखने वाला कचरा नहीं है। समुद्री प्लास्टिक कचरे से पीएफएएस और भारी धातुएं निकलती हैं। ये रसायन पानी में मिल जाते हैं। छोटे तालाब और झीलें बंद प्रणाली होती हैं। वहां प्रदूषक बाहर नहीं जा पाते और समय के साथ उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। पक्षी और जानवर इस पानी को पीते हैं। इंसान भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, जब वे ऐसे जानवरों का मांस खाते हैं जो प्रदूषित क्षेत्र में चरते हैं। पीएफएएस को ॅरएवर केमिकल कहा जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध देश नॉर्वे भी इस चुनौती का सामना कर रहा है। वहां सरकार ने प्लास्टिक रणनीति और कुछ योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में उत्पादकों की जिम्मेदारी, कचरा प्रबंधन में सुधार और मछली पकड़ने के जाल की निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने समुद्री प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिए धन भी दिया है। लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में अब कम धन दिया जा रहा है। स्वयंसेवक और संगठन लगातार सफाई करते हैं, फिर भी हर साल नया कचरा समुद्र से बहकर तट पर आ जाता है। इसका मतलब है कि सफाई जरूरी है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। प्लास्टिक उद्योग कई देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। प्लास्टिक सस्ता, हल्का और टिकाऊ होता है। इसका उपयोग पैकेजिंग, दवाइयों, निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों में होता है। अगर उत्पादन कम किया जाए, तो उद्योगों और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। इसी कारण सरकारें कठोर कदम उठाने में हिचकिचाती हैं। आज अधिकतर प्रयास सफाई पर आधारित हैं। समुद्र तटों से कचरा हटाया जाता है। लेकिन असली समस्या प्लास्टिक का उत्पादन और उसका अत्यधिक उपयोग है। जब तक उत्पादन कम नहीं होगा, तब तक प्रदूषण जारी रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। लेकिन चुनावी राजनीति अक्सर छोटी अवधि की सोच पर आधारित होती है। प्लास्टिक उत्पादन कम करने के फायदे लंबे समय में दिखेंगे, जबकि आर्थिक लागत तुरंत दिखेगी। इसलिए कई सरकारें बड़े बदलाव से बचती हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक प्रदूषण एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। समुद्री धाराएं एक देश का कचरा दूसरे देश के तट पर ले जाती हैं। इससे जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है। 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य तय है, पर कई देशों में ठोस क्रियान्वयन अब भी सीमित है।प्लास्टिक प्रदूषण हमारे समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। लक्ष्य तय करना पहला कदम है, लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है।अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रकृति की रक्षा के लिए हमें शब्दों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन असली बदलाव केवल कार्रवाई से आएगा।

मध्य प्रदेश के हाथी गलियारों को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने की याचिका दायर

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित दो हाथी गलियारों को इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) के रूप में घोषित करने की याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की गई है। इसके तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी से छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तक का गलियारा और मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली से झारखंड के पलामू तक का फैले गलियारे को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित करने का आग्रह किया गया है। एनजीटी ने याचिका पर विचार करने के बाद संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

एनजीटी की प्रधान पीठ में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद ने 26 फरवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि इन दो हाथी गलियारों का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इन गलियारों को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित करने के लिए बाद में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने पहले ही पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ कुछ अनुमतियों को चुनौती दी थी, लेकिन अब वह इस याचिका को केवल इन गलियारों के इको-सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचना करने पर केंद्रित कर रहे हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि संसद में 2018 में उठाए गए सवालों के संदर्भ में इन गलियारों का विवरण भी सार्वजनिक किया गया था, लेकिन कार्यवाही में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। याचिका के मुताबिक, लोकसभा में 2018 में सभी हाथी गलियारों को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करने के संबंध में सवाल उठाए गए थे और इसके जवाब में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए गलियारों की सूची का खुलासा भी किया गया था। यह मामला पहले भी एनजीटी की एक पिछली सुनवाई में उठा था, जिसमें विशेष रूप से हाथी गलियारों के सुरक्षा को लेकर मंत्रालय को निर्देश दिए गए थे। 14 नवंबर 2018 को एनजीटी की प्रधान पीठ द्वारा जारी आदेश में देश भर में सभी हाथी गलियारों को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करने की आवश्यकता की बात की गई थी। याचीकर्ता ने 16 मई, 2019 के एक आदेश का उल्लेख किया। आदेश में कहा गया था, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी संरक्षण क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर संबंधित हाथी-आधारित राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया था और अन्य किसी भी बचे हुए मुद्दे पर भी काम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया था, जो हाथी संरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर रही है। हालांकि, इस संदर्भ में कोई नया कदम उठाया नहीं गया है। मध्य प्रदेश के इन गलियारों का प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचना में विलंब से हाथी संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर एनजीटी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य और दस्तावेजों पर विचार किया और इसे अगले सुनवाई के लिए 26 मई 2026 को तय किया है। एनजीटी ने इस मामले में कहा है कि सभी उत्तरदाताओं को एक सप्ताह पहले अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को भी उत्तरदाताओं को सेवा का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण में भी जुटे बाल कवि कार्तिक

गोपेश्वर। गढ़वाली बोली-भाषा के संरक्षण के साथ ही बाल कवि कार्तिक तिवारी पर्यावरण संरक्षण में भी जुटे हुए हैं। सोमवार को होली पर्व की पूर्व संध्या पर कार्तिक ने बंज्वाणी के जंगल में पौधरोपण कर धरती को हरभरा बनाने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने का संदेश दिया। कार्तिक अभी तक दो हजार से अधिक पौधों का रोपण कर चुके हैं। श्रीरामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर में नौवीं कक्षा के छात्र कार्तिक (13) को छोटी उम्र से ही पर्यावरण और बोली भाषा के संरक्षण की ललक है। कार्तिक की माता तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित मीना तिवारी भी पर्यावरण संरक्षण में जुटी हैं। कार्तिक भी उन्हीं के पदचिह्नों पर चल रहे हैं। कार्तिक अभी तक गढ़वाली बोली-भाषा के संरक्षण पर कई कविताएं भी लिख चुका है। बीते दिनों वसंत उत्सव में राज्यपाल भवन लोक भवन में कार्तिक ने अपना संबोधन गढ़वाली बोली में किया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

बाड़मेर के तेल क्षेत्र में काला धुआं बना खतरा, ग्रामीणों ने उठाए पर्यावरण पर सवाल

बाड़मेर राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र से उठता काला धुआं चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां केयर्न वेदांता द्वारा वर्ष 2009 से क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का उत्खनन किया जा रहा है. लेकिन प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर कंपनी फ्लेयरिंग प्रक्रिया के तहत गैस को ऊंची चिमनियों से जला रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इन चिमनियों से लगातार घना काला धुआं निकलता है जो दिन में भी साफ दिखाई देता है. यह धुआं आसमान में दूर तक फैल जाता है और आसपास के गांवों की हवा को प्रभावित कर रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो यह पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हो सकता है. गांवों में रहने वाले लोग आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं. कई परिवारों का कहना है कि बच्चों को आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है. ग्रामीणों को डर है कि अगर यही स्थिति रही तो लंबे समय में गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कंपनी और प्रशासन को कई बार शिकायत दी है. हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती. इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. स्थानीय नागरिकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों से साइट पर जांच की मांग की है. उनका कहना है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण कृषि और जन स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ेगा. प्रशासन से उम्मीद है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच कर उचित समाधान निकाला जाएगा ताकि क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके.

इको-एंजायटी- भविष्य की चिंता और जलवायु परिवर्तन बनी युवाओं के लिए चुनौती, एक सर्वे में चौंकाने वाली बातें आईं सामने

नई दिल्ली। भारत और दुनिया भर के युवाओं में भविष्य को लेकर असुरक्षा और %इको-एंजायटी% (पर्यावरणीय चिंता) तेजी से बढ़ रही है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट स्टेट आफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण और आर्थिक अस्थिरता आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे हैं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। सीएसई के वरिष्ठ विशेषज्ञ रिचर्ड महापात्र ने कहा, पर्यावरण के प्रति लापरवाही युवाओं को सबसे अधिक परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, %पिछले 25 वर्षों में पैदा हुए लोगों ने शायद कभी %सामान्य% जलवायु का अनुभव ही नहीं किया है। हीटवेव से लेकर चक्रवात और बाढ़ तक, पृथ्वी की धड़कन बदल गई है और युवा इसे गहराई से महसूस कर रहे हैं। सर्वेक्षण में शामिल युवाओं ने %बेबसी%, %डर%, %दुख% व %विश्वासघात% जैसे शब्दों का उपयोग अपनी मानसिक स्थिति बताने के लिए किया। रिपोर्ट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक असमानता और युवाओं के अनिश्चित भविष्य पर भी प्रकाश डालती है। आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच बढ़ती जीवन लागत के कारण 150 देशों में लगभग 12,500 विरोध प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि ये प्रदर्शन किसी चुने हुए नेतृत्व द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं। इसके बजाय, विकास से जुड़े मुद्दे और भविष्य की अनिश्चितता युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। बुनियादी अस्तित्व के साधनों की कमी और राजनीतिक तंत्र की विफलता के खिलाफ युवा अब खुद अपना नेतृत्व कर रहे हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट यह स्पष्ट संदेश देती है कि यदि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता को गंभीरता से नहीं लिया, तो युवाओं का यह असंतोष आने वाले समय में और भी उग्र रूप ले सकता है।

बढ़ते ओजोन से कटक में स्थिति बेहद खराब, शिलांग में 200 के पार एक्यूआई

शिलांग। भारत की 96 फीसदी आबादी यानी 133 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जहां पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी मानकों से सात गुणा खराब है 02 मार्च 2026 को देश में हवा का हाल गंभीर तस्वीर पेश करता है। ओजोन की बढ़ती मात्रा के कारण कटक 302 एक्यूआई के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से करीब 400 फीसदी अधिक है। बीते 24 घंटों में यहां प्रदूषण 21 अंकों तक बढ़ा। दूसरी ओर श्रीनगर 28 एक्यूआई के साथ सबसे साफ शहर रहा, जिससे कटक की स्थिति करीब दस गुना बदतर नजर आती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 236 शहरों के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के 53 फीसदी शहरों में हवा चिंताजनक है, जबकि महज 2.9 फीसदी शहरों में ही हवा साफ है। हरियाणा के पांच शहर देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। यह रुझान बताता है कि प्रदूषण अब स्थानीय नहीं, बल्कि व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। विश्लेषण के मुताबिक 02 मार्च 2026 को देश में कटक सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 302 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इससे एक दिन पहले यानी 01 मार्च को कटक में एक्यूआई 281 था। यानी बीते 24 घंटों में प्रदूषण के स्तर में 21 अंकों का उछाल आया है। रुझानों में सामने आया है कि कटक की हवा में ओजोन पूरी तरह हावी है। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है। कटक में स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 400 फीसदी अधिक है।

दूसरी तरफ देश में श्रीनगर की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 28 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर कटक की तुलना श्रीनगर से करें तो वहां स्थिति 10 गुणा खराब है। इससे पहले कल देश में चरखी दादरी की स्थिति सबसे खराब थी, जब एक्यूआई 296 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज पांच अंकों के सुधार के साथ वहां सूचकांक घटकर 291 पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में मामूली इजाफा हुआ है। दिल्ली में जहां कल एक्यूआई 191 दर्ज किया गया था, जो आज बढ़कर 193 पर पहुंच गया। मतलब कि पिछले 24 घंटों में सूचकांक में दो अंकों का उछाल दर्ज किया गया। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी भी मानकों से 200 फीसदी अधिक खराब है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में कल से प्रदूषण में गिरावट आई है। फरीदाबाद में कल जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 193 दर्ज किया गया था, जो आज घटकर 192 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता आज भी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 02 मार्च 2026 को 236 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां महज 2.9 फीसदी शहरों में हवा साफ है। वहीं 44.1 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 53 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज हवा चिंताजनक बनी हुई है। बता दें कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 36.4 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरी तरह संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की बात करें तो इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्थिति जस की तस है। वहीं खराब गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में करीब 16.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जोकि चिंता का विषय है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में चरखी दादरी (291) दूसरे जबकि बल्लभगढ़ (270) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह 248 अंकों के साथ धारूहेड़ा चौथे स्थान पर है। भिवाड़ी-बहादुरगढ़ में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 242 और 241 अंकों के साथ पांचवें और छठे पायदान पर हैं। गुरुग्राम (240) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में मंडीदीप (236), अंगुल (230), मंडी गोबिंदगढ़ (227) भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के पांच शहर (चरखी दादरी, बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, बहादुरगढ़, गुरुग्राम) शामिल हैं। विश्लेषण से यह भी पता चला है कि चरखी दादरी, धारूहेड़ा, भिवाड़ी, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मंडीदीप, मंडी गोबिंदगढ़, वडोदरा, फरीदाबाद, रायबरेली, गुम्मिडीपूंडी, मानेसर, पानीपत, जींद, बर्नीहाट, नलबाड़ी, हाजीपुर, कुरुक्षेत्र, तालचेर, वातवा, पंचगांव, इंदौर, चिक्काबल्लापुर, सोनीपत, राउरकेला, अगरतला, हापुड़, लखनऊ, आसनसोल, नारनौल, बारीपदा, करनाल, रूपनगर, उज्जैन, मुजफ्फरपुर, पुदुचेरी, मोतिहारी, सोलापुर आदि शहरों की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) हावी हैं।

मऊ में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता ढेर-खेतों और पर्यावरण के लिए बन रहा बड़ा खतरा

मऊ जिले में प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरे का बढ़ता अंबार गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह कचरा न केवल सड़कों और खाली भूखंडों पर जमा हो रहा है, बल्कि अब किसानों के खेतों तक भी पहुंच गया है।

खेतों में प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बैग मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और भूजल भी प्रदूषित हो रहा है, जो स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रदूषण भविष्य में बड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों के लिए यह कचरा कई बीमारियों का स्रोत बन सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक के उचित निपटान और पुनर्चक्रण के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान चलाना महत्वपूर्ण है ताकि इस खतरे को कम किया जा सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008